Termination of services of Executive Director and Director

1538. SHRI MAHENDRA PRASAD:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will_ the Minister of COM-

(a) whether it is a fact that the services of Executive Director of the Centre for Development of Telematics and its Director have been terminated by Government; and

(b) if so, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COM-MUNICATIONS (SHRI JANESH-WAR MISHRA): (a) and (b) It
was decided not to continue with the services of Shri G. B. Meemamsi, Executive Director, C-DOT since he had cross 60 years of age which is the maximum prescribed as per the by-laws of C-DOT. The tenure of Shri D. R. Mahajan, Director, C-DOT had expired and it was decided not to grant any extension to him.

1539. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of SURFACE TRANS PORT be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh have sent proposals for construction of a bridge on river Godavari connecting Obalapur village in Karimnagar District and Badamldrthi Village in Adilabad District under Central Road Fund;

(b) if so, whether Government have given their approval;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNI-KRISHNAN): (a) Yes, Sir.

(b)to(d) As the actual augmentation of Central Road Fund against which the proposal were invited has not yet taken place, the same have not been processed for approval.

Funds for National Highway

1540. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
SHRI K. K. VEERAPPAN:
SHRIJ. S. RAJU:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state the amount of the funds sanctioned for NH. 7 bye-pass for Namakkal in Salem Karur Road and by when the work is proposed to be inaugurated ?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNI-KRISHNAN): On receipt of proposal for Namakkal byepass, the State Government has been requested first to establish detailed justification of the byepass on the basis of traffic requirements etc. Namakkal byepass did not figure in the 7th
PLAN NOT IS INCIUDED IN THE ANNUAL PLAN FOR 1990-91
Plan for 1990-91.

हिन्दी के विकास के लिए योजना

1541. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिये कोई व्यापक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख)

हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास, प्रोन्नति और प्रसार के लिए सरकार कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाए इस प्रकार है :—

(1) अहिन्दी भाषी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता (दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई इस योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 हिन्दी शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं और 31 हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को इसका लाभ मिला है)।

(2) हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की प्रोन्नति और प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता (अनुमोदित व्यय अनुमान के 75 प्रतिशत की दर से सहायता दी जाती है)।

(3) भारतीय भाषाओं में पुस्तकें छापने के लिए सहायता (अनुमोदित व्यय अनुमान के 80 प्रतिशत की दर से)।

(4) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन) द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षण।

(5) पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरण के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद (इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 200 प्रतियां खरीदी जाती हैं)।

(6) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा शिक्षकों को हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण।

(7) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम (प्रति वर्ष लगभग 14,000 विद्यार्थी नामांकित किए जाते हैं)।

(8) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोषों का निर्माण (20 द्विभाषी एवं बहुभाषी शब्दकोष निकाले जा चके हैं और 24 द्विभाषी शब्दकोषों का संकलन किया जा रहा है)।

(9) शिक्षा विभाग के अधिन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिन्दी और अन्य भाषाओं की शब्दावलियों का संकलन और निर्माण (विभिन्न शब्द संग्रहों में 5 लाख से अधिक शब्दों का संकलन आयोग द्वारा किया जा चुका है)।

(10) विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के शिक्षकों को हिन्दी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिलाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन।

(11) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के मार्ग-दर्शन में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यक्रम पुस्तकों का निर्माण (लगभग 9000 पुस्तकें इस योजना के अंतर्गत निकाली जा चुकी है)।

(12) तरक्की उर्दू ब्यूरो (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, का अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा उर्दू का विकास और प्रोन्नति।

(13) सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन और सिंधी में प्रकाशन निकालकर सिंधी भाषा का विकास और प्रोन्नति।

(14) संस्कृत और अन्य क्लैसिक भारतीय भाषाओं, जैसे प्राचीन तमिल, पाली, अरबी, फारसी, इत्यादि के विकास और प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं

को वित्तीय सहायता तथा संस्कृत विद्या-पीठों में संस्कृत का अध्यापन आदि।

2. राजभाषा विभाग भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के राज-भाषा के रूप में प्रयोग के क्षेत्र के विकास के कई कार्यक्रमों को चलाने में क्रियाशील है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कुछ इस प्रकार है :—

(1) द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) प्रयोग के लिए आधुनिक यांत्रिक सुविधाओं और कार्यालय उपस्करों का विकास।

(2) सभी सरकारी कोडों, मैनुअलों तथा गैर-सांविधिक प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी में अनुवाद।

(3) हिन्दी का ज्ञान न रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण।

(4) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अंग्रेजी के टंककों और आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण।

(5) राजकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रचार।

3. विद्यार्थी विभाग (राजभाषा खंड), विधि और न्याय मंत्रालय, विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के कार्यक्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों तथा सांविधिक साहित्य के हिन्दी अनुवाद के कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से चला रहा है। इसी प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियमों आदि का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है।

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में समारोह

1542. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में प्रजातंत्र की बहाली की पूर्वसंध्या पर नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में कोई समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) क्या नेपाल कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय दूतावास से सम्पर्क किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय दूतावास की क्या प्रतिक्रिया था ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हमारा राजदूतावास नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली से पहले, उसके दौरान तथा उसके बाद भी वहां की राजनीतिक विचारधारा के सभी वर्गों के लोगों से जिसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल है, बराबर सम्पर्क बनाए रहा हैं।

Circular issued by D. G. of Punjab Police

1543. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the staff circular issued by the Director General of Punjab Police on 1st April, 1990 offering a reward of Rs. 40, 000/- for the arrest/apprehension of each of the 41 wanted terrorists listed in it; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFI AIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir.

(b) The Circular in qustion announced reward for showing exemplary courage in the course of duty in effecting the arrest/apprehension of 41 wanted terrorists, who had been evading arrest, for maintenance of public order in the State.